

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

मसालारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—बाटु 1  
PART I—Section 1

प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

ल. 68] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 1994/वैशाख 27, 1916

No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 1994/VAISAKHA 27, 1916

पांचवां केन्द्रीय बैठन आयोग

ग्रहिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 1994

फाइल सं. ए.-11019/2/94-प्रशा. 1 (ब. आ.).—भारत सरकार ने ग्राहने संकल्प मं. 5 (12)/ई. 3/93 दिनांक 9 अप्रैल, 1994 द्वारा संशर्भ के तिम्म नियां सहित पांचवें केन्द्रीय बैठन आयोग का गठन कर दिया है:—

(क) सिद्धांतों, जो पारिश्रमिक की संरक्षना को ग्राहित करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की उन शर्तों को प्रस्तुत करना, जिनका आर्थिक अभिप्राय होगा।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित संबंधों की सेवा शर्तों तथा पारिश्रमिक की वर्तमान सरचना की उनकी उपलब्ध सभों के कूल पैकेट को विचार में लेते हुए जांच करना तथा उनमें परिवर्तनों का सुझाव देना, जो बांधनीय एवं व्यवहार्य हों—

- (1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी—आधारिक एवं गैर आधारिक,
- (2) अखिल भारतीय सेवा में संबंधित कार्मिक,
- (3) सशम्भव बलों से संबंधित कार्मिक,
- (4) केन्द्रप्रायित धोकां के कार्मिक, तथा
- (5) भारतीय मर्वांच्च न्यायालय न्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।

(ग) पेशनधारियों हेतु एक समचित पेशन संरचना प्रदान करने के उद्देश्य में मृत्यु एवं अवकाश प्राप्ति लाभों महित मोजूदा पेशन मंगवना की जांच करना तथा उससे मंवंधिन अनशंसाएं करना, जो बांधनीय एवं व्यवहार्य हों।

(घ) कार्य के तरीकों तथा कार्य परिवेश साथ ही उस प्रकार के भरों तथा लाभों के किसीजो जो वेतन के अतिरिक्त उपरोक्त संबंधों को वर्तमान में उपलब्ध हैं, की जांच करना तथा प्रशासन में दक्षता विकसित करने, अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम करने तथा सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलनम बनाने के उद्देश्य में उनका औचित्यस्थापन तथा सरलीकरण का सुझाव देना।

(ङ) अन्य संबद्ध तथ्यों के साथ गज्य सरकारी इत्यादि के अधीन उपलब्ध प्रचलित वेतन संरचना तथा अवकाशप्राप्ति लाभों, देश के आर्थिक हालात, केन्द्रीय सरकार के संसाधनों तथा उन पर मांगों, जैसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा मुद्राः ग्राधिक प्रवंथ की अपेक्षाओं के कारण को विचार में रखते हुए उपरोक्त प्रत्येक पर अनुशंसाएं करना।

2 आयोग यभी सगठनों, श्रम संघों, सम्यानों, अन्य संगठनों तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्त भास्तु पर उनके विचार निहित मेमोरेंडम भेजे जिनमें प्रत्येक विषय पर पृथक रूप से विचार व्यक्त हो, प्रत्येक पैराग्राफ की संस्था लिखी हो। आयोग वरीयतः एक कंप्यूटर का फलापी पर इन मेमोरेंडा सामग्री को प्राप्त करना होगा। विकल्प रूप में ऐसे मेमोरेंडा की सात प्रतियां सदम्य सचिव, पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग, विज्ञान भवन अनैकत्ती, एम. ए. रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाएं, जो 15 जूलाई, 1994 तक या उसमें पूर्व उनके पास पहुंच जानी चाहिए।

एम. के. काव, सदस्य सचिव  
पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

## FIFTH CENTRAL PAY COMMISSION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 1994

F. No A-11019/2/94-Ad. I(PC).—Government of India vide its Resolution No. 5(12)/E. III/93, dated the 9th April, 1994 have constituted the Fifth Central Pay Commission with the following terms of reference :—

- (a) To evolve the principles which should govern the structure of emoluments and those conditions of service of Central Government employees which have a financial bearing.
- (b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of the following categories of Government employees, taking into account the total packet of benefits available to them and suggest changes therein which may be desirable and feasible :—
  - (i) Central Govt. employees—industrial and non-industrial;
  - (ii) Personnel belonging to the All India Services;
  - (iii) Personnel belonging to Armed Forces;
  - (iv) Personnel of the Union Territories; and
  - (v) Officers and employees of the Supreme Court of India and the High Court of Delhi.
- (c) To examine, with a view to having a proper pension structure for pensioners the existing pension structure including death-cum-retirement benefits and make recommendations relating thereto which may be desirable and feasible.
- (d) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the aforementioned categories in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration, reducing redundant paper work and optimising the size of the Government machinery.
- (e) To make recommendations on each of the foregoing having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure and retirement benefits available under the State Governments etc., economic conditions in the

country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of economic and social development, defence and national security and requirements of sound fiscal management.

2. The Commission invites all associations, unions, institutions, other organisations and interested individuals to send memoranda containing their views on the aforesaid matters, dealing with each subject separately, numbering the paragraphs. The Commission would prefer to have this memoranda material on a computer floppy. Alternatively, seven copies of such memoranda may be sent to the Member Secretary, Fifth Central Pay Commission, Vigyan Bhavan Annexe, M.A. Road, New Delhi-110 001, so as to reach him on or before 15th July, 1994.

M.K. KAW, Member-Secretary  
Fifth Central Pay Commission